DSSSB TGT & PGT

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

ROJGAR With ANKIT

Part-B

SCHOLAR BATCH

MODERN HISTORY

भारत छोड़ो आंदोलन

Part -2

LIVE 29-07-2024 04:00 PM

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे एक अन्य विश्वयुद्ध की परिस्थितियां बनने लगी थी। संभावित युद्ध की तैयारी में भारत की ब्रिटिश सरकार ने अप्रैल, 1939 ई० को मिस्र और सिंगापुर में भारतीय सेनाओं को भेजा था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और यह कहा कि भारतीय जनता और कांग्रेस से सलाह-मशविरा किए बगैर भारतीयों को बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए।

- 11 सितंबर, 1939 ई० को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।

- 3 सितंबर को भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने भारत को भी मित्र राष्ट्र की ओर से इस विश्व युद्ध में संलग्न घोषित कर दिया।

- अंग्रेज़ों ने कहा कि इस युद्ध द्वारा प्रत्येक जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा।

- कांग्रेस ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी युद्ध में शामिल करने का विरोध किया।

- कांग्रेस ने तब ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य घोषित करने को कहा। साथ ही इस बात की भी घोषणा करने को कहा कि युद्धोपरांत भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा।

- परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया।

- 22 अक्टूबर, 1939 ई० को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने लगभग 28 माह के शासनकाल के बाद आठों प्रांतों से अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया।

- इन सभी प्रांतों में धारा 93 के अंतर्गत एक बार फिर से गवर्नरों का शासन लागू कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इससे खुश होकर 22 दिसंबर, 1939 को 'मुक्ति दिवस' (Day of deliverance) और 'धन्यवाद दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की।

मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन

23 मार्च, 1940 ई० को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 'द्विराष्ट्र के सिद्धांत' का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे कि अगले दिन के समाचार-पत्रों ने 'पाकिस्तान प्रस्ताव' के नाम से प्रकाशित किया।

- मोहम्मद इकबाल ने जवाहर लाल नेहरू के साथ हुए बात-चीत के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी तुलना करते हुए कहा था- " नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ ।"

- उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव में कहीं भी 'पाकिस्तान' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था।

- इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था, जबकि फज्लुलहक ने इसे प्रस्तुत किया और खलीकउज्जमां ने इसका समर्थन किया।

- इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि कभी-कभी भ्रमवश यह मान लिया जाता है कि 'पाकिस्तान' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था, जो कि ग़लत है।

- वास्तव में इस शब्द का प्रयोग पहली बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र (चौधरी रहमत अली ने 1933 ई० में किया था, न कि इकबाल ने ।

- मोहम्मद इकबाल ने केवल यह बात कही थी कि भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर उसे भारत के अंदर ही एक स्वायत्त प्रांत के रूप में मान्यता मिले।

चौधरी रहमत अली ने जिस 'पाकिस्तान' शब्द का प्रयोग किया था, उसका तात्पर्य निम्नलिखित था-

- P -Punjab
- A - Afghan Province
- K - Kashmir
- S - Sindh
- tan - Bluchistan

लिनलिथगो प्रस्ताव (8 अगस्त, 1940 ई०)

- दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की एक कोशिश ब्रिटिश सरकार के द्वारा 'लिनलिथगो प्रस्ताव' के रूप में की गई।

8 अगस्त 1940

- चूंकि यह प्रस्ताव अगस्त में घोषित किया गया था, इसलिए इसे 'अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है।

वायसराय लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव के अंतर्गत निम्नलिखित घोषणाएं की-

a. अनिश्चित भविष्य में भारत का दर्जा एक डोमीनियन स्टेटस का।

b. युद्धोपरांत एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन।

c. वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय हो जाने थे।

d. एक युद्ध सलाहकार परिषद् का गठन।

- भारतीयों ने इसको स्वीकार करने से इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें अनिश्चित भविष्य में डोमीनियन स्टेटस की बात की गई थी।

- ब्रिटिश सरकार ने यद्यपि इसी प्रस्ताव में (पहली बारे भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, तथापि यह प्रस्ताव भारतीयों को प्रभावित नहीं कर सका और यह असफल हो गया।

- जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसमें जिस 'डोमीनियन स्टेटस' की बात की गई थी, यह 'दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील' की भांति है।

- जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेसजनों की उस समय की निराशा एवं विक्षोभ का वर्णन 'दो रास्ते' नामक एक लेख में किया है- " इस प्रस्ताव घोषणा ने हमारे दिलों को जोड़े रखने वाले रहे - सहे मुलायम धागों को भी तोड़ दिया। "

व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन

- कांग्रेस ने विश्वयुद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता के असंतोष को व्यक्त तो करना चाहते थे, परंतु युद्ध के दौरान सरकार की संकटपूर्ण स्थिति से लाभ भी उठाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जनांदोलन के बजाय नैतिक विरोध करने के एक तरीके के रूप में उपरोक्त आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।

- इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को गलत साबित करना था, कि भारत युद्ध की तैयारी में पूरी तरह से मदद दे रहा था।

- इस आंदोलन में जिस सत्याग्रही का चयन किया जाता, उन्हें सरकार विरोधी और युद्ध विरोधी भाषण करने थे, वह भी इसके स्थान और समय की पूर्व सूचना सरकार को देने के बाद।

- इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 ई० को महाराष्ट्र के (वर्धा जिले में स्थित पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की।

- इसके दूसरे सयग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को 'दिल्ली चलो का आंदोलन' कहकर भी पुकारा जाता है।

क्रिप्स मिशन एवं उसका प्रस्ताव

❖ मित्र राष्ट्रों के दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा (11 मार्च, 1942 ई० को भारत की संवैधानिक प्रगति से संबंधित कार्य करने हेतु एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई।

- आंदोलन की सीमित प्रकृति के कारण यह आंदोलन अधिक सफल नहीं हो सका।

❖ इस मिशन की घोषणा कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलीन डी० रूजवेल्ट, चीनी राष्ट्रपति च्यांग काई शेक और आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ईवाट्ट ने अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

❖ यह मिशन 23 मार्च, 1942 ई० को भारत पहुंची।

❖ इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे।

भारत की विभिन्न शक्तियों से बातचीत करने के पश्चात् (30 मार्च, 1942 ई० को इसने अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई –

a. भारत का दर्जा डोमीनियन स्टेटस के समान होगा, जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा।

b. भारत के लिए एक संविधान की भी रचना की जाएगी, जिसका निर्माण एक (संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इस संविधान सभा के गठन हेतु एक चुनाव मंडल की स्थापना की जानी थी, जिसमें देशी रियासत और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि जहां मनोनयन के द्वारा वहीं ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनधि चुनाव के द्वारा आने थे।

c. देशी रियासत और ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना या न होना उसकी इच्छा पर निर्भर था।

d. संविधान सभा के सदस्यों की संख्या इस चुनाव मंडल के 1 / 10 भाग होना था।

- तात्कालिक प्रावधान के रूप में यह कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी के सारे सदस्य भारतीय हो जाएंगे, जिन्हें रक्षा संबंधी कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे।

- इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। इसके दूरगामी और तात्कालिक दोनों प्रावधानों से वह असंतुष्ट थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का यह कहना था कि कांग्रेस वास्तव में यह चाहती थी कि ऐसी प्रक्रिया चला दी जाए कि कार्यकारिणी के सदस्य वास्तविक मंत्रिमंडल के रूप में, जबकि गवर्नर जनरल सांवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करे।

❖ समझौता करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के एक प्रतिनिधि कर्नल लुई जॉन्सनन ने भी क्रिप्स के साथ मिलकर 'क्रिप्स-जॉन्सन फॉर्मूला' नामक एक योजना प्रस्तुत की, लेकिन बात नहीं बन सकी और अंततः क्रिप्स मिशन असफल हो गया।

- गांधीजी ने इस मिशन को 'उत्तर दिनांकित चेक' (Post Dated Cheque) कहकर पुकारा, जबकि संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने उसके 'दिवालिया होने वाले बैंक पर (On crashing Bank) जैसे शब्दों को जोड़ दिया।

- पट्टाभि सीतारमैया ने इस प्रस्ताव के बारे में कहा था-"क्रिप्स प्रस्ताव उस बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयत्न था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था । " पट्टाभि सीतारमैया ने इस प्रस्ताव को 'अगस्त प्रस्ताव का परिवर्द्धित संस्करण मात्र' कहा था।

❖ सी० राजगोपालाचरी ने मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल में क्रिप्स के प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया। यह एक प्रकार से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णय का खुला विरोध करना था।

❖ मौलाना आज़ाद ने तब उनसे उत्तर मांगा, क्योंकि एक सदस्य के नाते उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। सी० राजगोपालाचारी ने तब क्षमा मांगी और कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया ।

- मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की उसकी मांग को स्पष्टतः स्वीकार नहीं किया गया था।

- भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला अंतिम जनांदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था।

इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे-

- क्रिप्स मिशन की असफलता।
- जापानी सेना का भारत की सीमाओं तक पहुंचना ।
- बढ़ती हुई कीमतें और खाद्य आपूर्ति की कमी। भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के ऐसे युद्धों के लिये इस्तेमाल करना जिससे भारत का प्रत्यक्षतः कोई मतलब नहीं था ।

- अटलांटिक चार्टर की घोषणा को भारत के लिए न लागू किये जाने का ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का ऐलान।

- गांधीजी के परिवर्तित विचार ।

कांग्रेस कार्यकारिणी की इलाहाबाद बैठक

- 27 अप्रैल, 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक गांधी जी की अनुपस्थिति में इलाहाबाद में बैठक हुई। इसमें राजेन्द्र प्रसाद ने गांधी जी के विचारों पर एक प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन वल्लभ भाई पटेल, जे०वी० कृपलानी जैसे गांधीवादियों ने और नरेन्द्रदेव, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों ने की। राजेन्द्र प्रसाद ने कहा-

- "अंग्रेज़ी सरकार भारत की रक्षा में असमर्थ मालूम - पड़ती है, परंतु भारतीयों को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार भी देना नहीं चाहती। यदि अंग्रेज़ भारत को तुरंत छोड़ कर चले जाए, तो जापान के आक्रमण से भारत सुरक्षित बच जाएगा।"

- जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, भूलाभाई देसाई, आसफ अली तथा सी० राजगोपालाचारी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

- नेहरू एवं आजाद का यह मानना था कि जापानी आक्रमण यदि हो तो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। - अंग्रेज़ों के भारत छोड़कर चले जाने की स्थिति में देश की व्यवस्था भंग हो जाने का ख़तरा है और इसमें सुरक्षा को लेकर भी स्थिति विकट हो सकती है।

- एक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर) जो उस समय गांधी जी के साथ सेवाग्राम में ठहरे हुए थे और जिन्हें आज़ाद व नेहरू की आंदोलन के प्रति नकारात्मक रवैये के बारे में जानकारी थी, ने गांधी जी से एक प्रश्न किया- " यह संघर्ष करने के लिए आपके पास क्या कोई संगठन है?"

गांधी जी का उत्तर था-

"वह संगठन कांग्रेस है, लेकिन यदि वह साथ नहीं भी देती, तो मेरा अपना संगठन है और वह संगठन मैं स्वयं हूं। मैं एक लक्ष्य से पूर्णतः ओत-प्रोत हूं। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई संगठन नहीं मिलता, तो वह स्वयं में एक संगठन हो जाता है। "

उन्होंने आगे कहा-

"यदि कांग्रेस मेरे इस निर्णय में साथ नहीं देती, तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा।"

कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्धा बैठक

- वर्धा (महाराष्ट्र) में 7-14 जुलाई, 1942 ई० को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी।

- इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 'वर्धा प्रस्ताव' कहकर भी पुकारा जाता है !

- इस प्रस्ताव के तहत जिस आंदोलन को छेड़ा जाना था, उसे शीघ्र ही 'भारत छोड़ो आंदोलन' की संज्ञा दी गई।

- इलाहाबाद की बैठक में, गांधी जी की ओर से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विरुद्ध जो तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए थे, वही तर्क उन्होंने इस बैठक में भी प्रस्तुत किए, लेकिन महात्मा गांधी अपने निश्चय से नहीं डिगे। अंततः इन लोगों को गांधी जी के पक्ष में अपनी सहमति देनी पड़ी।

- नेहरू जी ने अपने सभी सदेहों का न केवल परित्याग किया, बल्कि महात्मा गांधी की बात को स्वीकार कर, उन्होंने एक नया नारा दिया, जिसमें गांधी जी ने जो कुछ सोचा, कहा एवं लिखा था, समाहित था ।

- उन्होंने भारत छोड़ो को 'खुले विद्रोह' की संज्ञा दी एवं गांधी जी ने इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई। नेहरू के समर्थन के बाद आज़ाद ने भी अपना रुख बदल दिया और उन्होंने भी 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

- परंतु, सैय्यद महमूद 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' के साथ अपनी सहानुभूति प्रदर्शित नहीं कर सके ।

- बाद में, जैसा कि विदित है, महमूद ने वायसराय को इस आशय का पत्र लिखकर अहमदनगर जेल से मुक्ति प्राप्त की कि वे भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरुद्ध थे एवं इसलिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया था।

Thank you.